



21 May, 2024

गुजरात भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम

संदर्भ: गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा पर विधायी अधिकार की सर्वोच्चता को महत्व देते हुए गुजरात भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम के संवैधानिकता की पुष्टि की है।

➤ गुजरात भूमि अधिग्रहण (निषेध) अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- **पूर्वव्यापी अपराधीकरण:** दिसंबर 2020 से प्रभावी कानून, सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों की "भूमि हड़पने" को पूर्वव्यापी रूप से अपराध मानता है।
- **सबूत का दबाव:** यह सबूत के दबाव को कम कर देता है, जिससे अभियुक्तों को भूमि पर अपना कानूनी अधिकार साबित करने की आवश्यकता होती है।
- **न्यूनतम सजा:** अधिनियम में उल्लंघन के लिए न्यूनतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही संपत्ति के जंत्री मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **व्यापक विधान:** यह कानून संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 जैसे मौजूदा कानून के तहत कार्यवाही को प्रतिस्थापित करता है, जिससे भूमि हथियाने के अपराध को एक विशेष कानून के तहत समेकित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** "शिकायतों का समयबद्ध और त्वरित निपटान" सुनिश्चित करना और किसानों और आम आदमी को भूमि-माफिया गतिविधियों से बचाना।
- **दायरा:** पूर्वव्यापी रूप से लागू और भूमि हड़पने के खिलाफ नागरिक और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों की अनुमति देता है।
- **रिवर्स बर्डन क्लॉज:** धारा 11 सबूत का उल्टा बोझ लगाती है, जब तक कि वे अन्यथा साबित न कर सकें, आरोपी को भूमि हड़पने वाला मान लिया जाता है।

➤ न्यायालय के फैसले और चुनौती के आधार:

- **चुनौती के लिए आधार:**
 - **प्रक्रियात्मक उल्लंघन:** याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि, कई केंद्रीय कानूनों के प्रति असहमति के कारण कानून को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है।
 - **प्रकट मनमानी:** याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कानून अस्पष्ट और मनमाना है, इसमें व्यक्तियों को वर्गीकृत करने और निजी अतिक्रमणों को सार्वजनिक भूमि हड़पने के साथ जोड़ने के लिए उचित आधार का अभाव है।
- **राष्ट्रपति की सहमति का तर्क:**
 - धारा 15 के "अधिभावी प्रभाव" खंड को केंद्रीय कानूनों के संभावित प्रतिकूल के रूप में देखा गया, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी।
 - उच्च न्यायालय ने "डॉक्टरिन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस" को लागू किया, यह निर्धारित करते हुए कि कानून मुख्य रूप से राज्य सूची (भूमि-संबंधित मामलों) की प्रविष्टि 18 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- **मनमानी तर्क:**
 - भूमि अधिग्रहण की व्यापक परिभाषा और अपरिभाषित शब्द "वैध हकदारी" को परिसीमन अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जे जैसे स्थापित सिद्धांतों पर उनके संभावित प्रभाव के लिए चुनौती दी गई थी।
- **उच्च न्यायालय का निर्णय:**
 - अदालत ने कहा कि कानून पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि भूमि पर अधिग्रहण करना तब तक "निरंतर अपराध" है जब तक यह अवैध तरीके से किया गया हो।

- विवादित भूमि पर आरोपी के वैध अधिकार को साबित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सबूत के बोझ को उलटने को बरकरार रखा गया।

साझा समृद्धि के लिए जल रिपोर्ट

संदर्भ: विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, पानी समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण पहुंच में असमानता, साझा समृद्धि के लिए खतरा है।

➤ जल रिपोर्ट का अवलोकन:

- इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच पर जारी की गई रिपोर्ट "साझा समृद्धि के लिए जल" जल संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच में बढ़ते अंतर को रेखांकित करती है, जो वैश्विक मानव और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है।
- जीवन की समृद्धि में पानी की मूलभूत भूमिका के बावजूद, लाखों लोगों के पास सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का अभाव है।

➤ प्रमुख आंकड़े:

- वर्ष 2022 में, 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, और 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी।
- इस समय कम आय वाले देश पिछड़ रहे हैं, वर्ष 2000 के बाद से अभी तक 197 मिलियन से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है।
- बुनियादी जल और स्वच्छता सेवाओं से वंचित दस में से आठ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

➤ क्षेत्रीय असमानताएँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच इस समय की सबसे गंभीर समस्या है।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास अफ्रीका के आधे से अधिक जल संसाधन हैं।
- जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में साहेल, दक्षिणपूर्वी अफ्रीका और दक्षिण और मध्य एशिया शामिल हैं।

➤ पहुंच में असमानता:

- यह रिपोर्ट उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच और देशों के भीतर सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्तियों के बीच व्याप्त असमानताओं को चिन्हित करती है।
- हाशिए पर रहने वाले समूह (लिंग, स्थान, जातीयता, नस्ल, राजनीतिक विश्वास और अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर) को भी जल सेवाओं तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ता है।

➤ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- विकासशील देश अधिक गंभीर सूखे और लंबे समय तक चलने वाली बाढ़ का अनुभव करते हैं, जिससे पोषण, स्कूल में उपस्थिति और आर्थिक कल्याण प्रभावित होता है।
- 800 मिलियन से अधिक लोग सूखे के उच्च जोखिम में हैं, जिनमें से दोगुने लोग बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं।

➤ समृद्धि के घटक:

- रिपोर्ट समृद्धि के चार परस्पर जुड़े घटकों की पहचान करती है: स्वास्थ्य और शिक्षा (मानव पूंजी), नौकरियां और आय, शांति और सामाजिक एकजुटता (सामाजिक पूंजी), और पर्यावरण (प्राकृतिक पूंजी)।

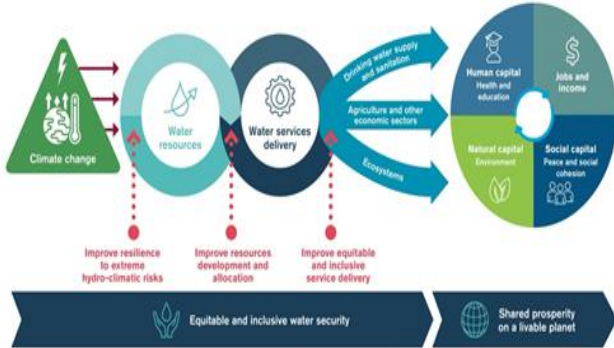
Face to Face Centres





21 May, 2024

FIGURE ES.1 Equitable and inclusive water security for shared prosperity on a livable planet



➤ आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

- बहते पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच पीढ़ियों तक शैक्षिक परिणामों में सुधार करती है।
- विकासशील देशों में, जल-सघन क्षेत्र नौकरियों और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, कम आय वाले देशों में 56% नौकरियां पानी पर निर्भर हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 20% है।
- उप-सहारा अफ्रीका में, 62% रोजगार पानी पर निर्भर है, और कम वर्षा अक्सर महत्वपूर्ण नकारात्मक जीडीपी वृद्धि का कारण बनती है।

➤ जल प्रबंधन और सामाजिक एकजुटता

- प्रभावी और न्यायसंगत जल प्रबंधन सामुदायिक विश्वास, समावेशिता और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे शांति में योगदान होता है।
- जल संसाधनों का कुप्रबंधन मौजूदा विवादों को बढ़ा सकता है या नए विवादों को जन्म दे सकता है।

जीवाणु रोगजनकों की प्राथमिकता सूची (BPPL)

संदर्भ: WHO की अद्यतन जीवाणु रोगजनक प्राथमिकता सूची प्राथमिकता वाले रोगजनकों को उनके उच्च बोझ, उपचार प्रतिरोध और प्रतिरोध फैलाने की क्षमता के कारण प्रमुख वैश्विक खतरों के रूप में पहचानती है।

➤ पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 में, WHO ने 13 जीवाणु रोगजनकों (फेनोटाइप) को सूचीबद्ध करते हुए, नए जीवाणुरोधी के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए पहला जीवाणु रोगजनकों की प्राथमिकता सूची विकसित किया।
- सूची बहु-मानदंड निर्णय विश्लेषण (एमसीडीए) पद्धति का उपयोग करके बनाई गई थी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो जटिल परिस्थितियों में व्यवस्थित और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा के लिए कई मानदंडों के आधार पर विकल्पों का मूल्यांकन करता है।

➤ 2024 अद्यतन:

- वर्ष 2024 WHO BPPL का विस्तार एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणु रोगजनकों के 15 परिवारों में 24 रोगजनकों को कवर करने के लिए किया गया है।
- यह अनुसंधान एवं विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए इन रोगजनकों को महत्वपूर्ण, उच्च और मध्यम प्राथमिकता समूहों में वर्गीकृत करता है।

Box 1. Operational definitions of priority categories in the 2024 WHO BPPL

Critical group	High group	Medium group
ABR bacterial pathogens that pose the highest threat to public health due to limited treatment options, high disease burden (mortality and morbidity) and increasing trends in resistance, with few or no promising candidates in the pipeline. Infections with pathogens in the critical category may also be uniquely difficult to prevent and are highly transmissible; the pathogens may have global mechanisms of resistance and/or MDR strains in certain populations or geographical areas.	ABR bacterial pathogens that are significantly difficult to treat, cause a substantial disease burden (mortality and morbidity), show increasing trends in resistance, are uniquely difficult to prevent, are highly transmissible and for which there are few potential treatments in the development pipeline. Although they may not be critical globally, pathogens in this category could be critical for some populations and in specific geographical areas.	ABR bacterial pathogens that are associated with moderate difficulty for treatment, a moderate disease burden (mortality and morbidity) and moderate trends in resistance, with unique issues for preventability or transmissibility and relatively more candidates for treatment in the pipeline. Similarly, while they may not be critical globally, pathogens in this category could be critical for some populations and in specific geographical areas.

➤ महत्व:

- बीपीपीएल एएमआर में अनुसंधान एवं विकास और निवेश को प्राथमिकता देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो प्रतिरोध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षेत्रीय रूप से तैयार की गई रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है।
- यह जीवाणुरोधी दवाओं के डेवलपर्स, शैक्षणिक और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, अनुसंधान फंडर्स, एएमआर आरएंडडी में निवेश करने वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी और एएमआर नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नीति-निर्माताओं को लक्षित करता है।

Fig 4. WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024

Critical group	High group	Medium group
- Enterobacterales carbapenem-resistant - Enterobacterales third-generation cephalosporin-resistant - Acinetobacter baumannii carbapenem-resistant - Mycobacterium tuberculosis, rifampicin-resistant* *B TB was included after an independent analysis with parallel criteria and subsequent application of an adapted MCDA matrix.	- Salmonella Typhi fluoroquinolone-resistant - Shigella spp. fluoroquinolone-resistant - Enterococcus faecium vancomycin-resistant - Pseudomonas aeruginosa carbapenem-resistant - Non-typhoidal Salmonella fluoroquinolone-resistant - Neisseria gonorrhoeae third-generation cephalosporin and/or fluoroquinolone-resistant - Staphylococcus aureus methicillin-resistant	- Group A Streptococci macrolide-resistant - Streptococcus pneumoniae macrolide-resistant - Haemophilus influenzae ampicillin-resistant - Group B Streptococci penicillin-resistant





21 May, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस



देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में:

- 1991 में चेन्नई के पास एक गांव श्रीपेरंबुदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या की याद में हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है।
- यह समाज और राष्ट्र पर आतंकवाद और हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है।
- 2024 का विषय "आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त: एक सुरक्षित और समावेशी भविष्य का निर्माण" है।

भारत के अटॉर्नी जनरल

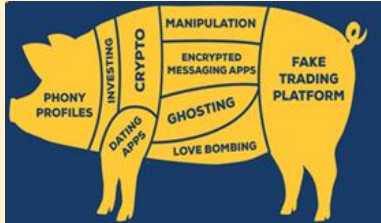


हाल ही में, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें स्थापना दिवस पर डिजिटल बाजारों में वैश्विक चुनौतियों और गोपनीयता और डेटा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में:

- भारत का अटॉर्नी जनरल (AG) देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए, अर्थात् वह पांच साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दस साल तक उच्च न्यायालय का वकील या एक प्रतिष्ठित न्यायविद् रहा हो।
- वह संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है और सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और हटाने के लिए कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है।
- उसे मतदान के अधिकार के बिना संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है और वह भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का हकदार है।
- वह सरकारी सेवक नहीं है और लाभ के पद की श्रेणी में भी नहीं आता है।
- अटॉर्नी जनरल को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है, बशर्ते यह कार्यालय के कर्तव्यों के साथ टकराव न हो।

पिग बूचरिंग घोटाला



हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग ने दो चीनी नागरिकों पर पिग बूचरिंग घोटाला चलाने का आरोप लगाया, जिसमें शेल कंपनियों के माध्यम से 73 मिलियन डॉलर से अधिक का धन शोधन किया गया था।

पिग बूचरिंग घोटाला के बारे में:

- पिग बूचरिंग घोटाला, जिसे शा झू पैन घोटाला के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी है जिसमें घोटालेबाज समय के साथ पीड़ितों का विश्वास हासिल करते हैं और फिर उनके पैसे चुरा लेते हैं।
- यह शब्द वध से पहले सुअर को "मोटा करने" की प्रथा से आया है और घोटालेबाज इस विचार का उपयोग पीड़ितों को एक धोखाधड़ी योजना में अधिक पैसा निवेश करने के लिए मनाने के लिए करते हैं।
- पिग बूचरिंग घोटाले में, घोटालेबाज एक नकली ऑनलाइन व्यक्तित्व बनाता है और ऑनलाइन संचार के माध्यम से पीड़ित के साथ विश्वास बनाता है।
- घोटालेबाज फिर पीड़ित को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकॉर्सी योजना में निवेश करने के लिए मना लेता है।

बाओबाब के पेड़



बाओबाब पेड़ों के बारे में:

- बाओबाब के पेड़ अपनी मुड़ी हुई शाखाओं के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जो उलटी जड़ों से मिलती जुलती हैं और ये मुख्य रूप से मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- बाओबाब वंश की जड़ें लगभग 21 मिलियन वर्ष पहले मेडागास्कर में पाई जाती हैं।
- इन पेड़ों के फैलाव को संभवतः तेरती हुई बीज की फलियों द्वारा सुगम बनाया गया था, जो हिंद महासागर की लहर जैसी समुद्री धाराओं की सहायता से लंबी दूरी तय करते थे, जो मेडागास्कर को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते थे।
- इन्हें "उल्टा" पेड़ भी कहा जाता है क्योंकि इनका शीर्ष उखाड़े हुए पौधे जैसा दिखता है जो उल्टा हो गया है।
- वे शुष्क सवाना आवासों में भोजन, आश्रय और घोंसले के स्थान प्रदान करके वन्यजीवों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे मनुष्यों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि उनके फल विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व और औषधीय गुण प्रदान करते हैं।
- बाओबाब पेड़ों के फूल रात्रि परागणकों और प्राइमेट्स जैसे मेडागास्कर में लीमर और अफ्रीका में झाड़ी शिशुओं को आकर्षित करते हैं।
- बाओबाब तेल में लिनोलिक एसिड, एक ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुँहासे में मदद कर सकते हैं।

Face to Face Centres





21 May, 2024

सुर्खियों में स्थल

ताइवान

हाल ही में, ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के लाई चिंग-ते ने स्वशासित द्वीप के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

ताइवान (राजधानी: ताइपे)

अवस्थिति : ताइवान, आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य, पूर्वी एशिया में पूर्व और दक्षिण चीन सागर के जंक्शन पर स्थित एक देश है।

राजनीतिक सीमाएँ: इसकी सीमाएँ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), जापान और फिलीपींस के साथ साझा होती हैं।

तटीय सीमाएँ: यह फिलीपीन सागर (पूर्व), पूर्वी चीन सागर (उत्तर), लूज़ोन जलडमरूमध्य (दक्षिण) और दक्षिण चीन सागर (दक्षिण पश्चिम) सहित जल निकायों से घिरा हुआ है।

भौतिक विशेषताएँ:

- ताइवान का सबसे ऊँचा स्थान यू शान है, जिसे जेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है।
- ताइवान की प्रमुख नदियों में जुओशुई, तमसुई, गाओपिंग, एगोंगडियन और ज़िंडियन नदियाँ शामिल हैं।
- कोयला, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, संगमरमर के कुछ भंडार और सोने, तांबे और लौह अयस्क के छोटे भंडार के साथ ताइवान में सीमित खनिज संसाधन हैं।



POINTS TO PONDER

- किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? — **ब्राज़ील**
- NOAA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दुनिया की कितनी मूंगा चट्टानें कोरल बलीचिंग से क्षति ग्रस्त हो गई हैं? — **60%**
- हाल ही में 'आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? — **गुवाहाटी**
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) से \$500 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ? — **एचडीएफसी बैंक**
- 'डायसन क्षेत्र' क्या है? — **किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना**

Face to Face Centres

